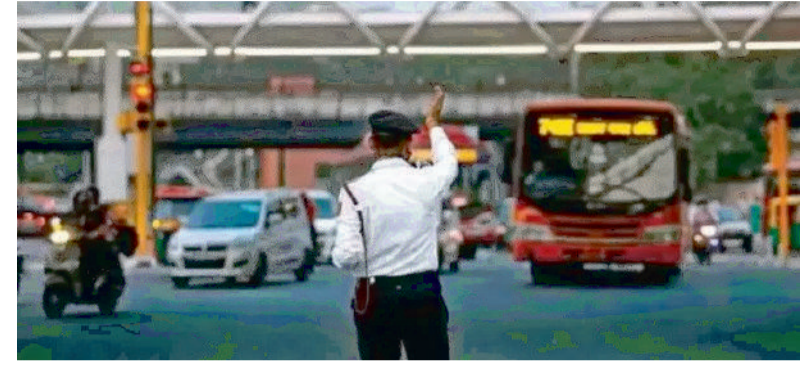


जीपीएस, पैनिक बटन, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना नहीं होंगे फिटनेस, पंजीकरण व प्रदूषण

दिल्ली हाफ मैराथन को लेकर 5 अप्रैल को कई मार्गों पर रहेगा डायवर्जन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की

दिल्ली में 5 अप्रैल को होने वाली PNB सॉलिडरेशन दिल्ली हाफ मैराथन के कारण दक्षिण दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने... और पढ़ें



नई दिल्ली। दिल्ली में रविवार को जेएलएन स्टेडियम में 'PNB सॉलिडरेशन दिल्ली हाफ मैराथन' का आयोजन होने जा रहा है। सुबह 5:30 बजे से शुरू होने वाले इस इवेंट के कारण दक्षिण दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक को रेगुलेट और डायवर्ट किया जाएगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर बताया कि मेहर चांद मार्केट सिग्नल, कोटला रेड लाइट, सेकंड एवेन्यू रोड-जोर बाग क्रॉसिंग, फोर्थ एवेन्यू रोड-जोर बाग क्रॉसिंग और लाला लाजपत राय कट (CBI बिल्डिंग) पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। भारी वाहनों की आवाजाही बी.पी. मार्ग और लोधी रोड पर सुबह 5 बजे से 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इन इलाकों में बी.पी. मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड, सेकंड एवेन्यू रोड और फोर्थ एवेन्यू रोड पर भारी जाम की आशंका है। इमरजेंसी वाहनों (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस आदि) को फ्री पैसेज दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जहां संभव हो बी.पी. मार्ग और सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड से बचने की सलाह दी गई है।

इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
मेहर चांद मार्केट सिग्नल: सेवा नगर, जोर बाग एवं आईएनए से आने वाले भारी वाहनों को फोर्थ एवेन्यू रोड एवं सेवा नगर मार्केट रोड के रास्ते अरोबिंदो मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
कोटला रेड लाइट: कोटला मुबारकपुर, डिफेंस कॉलोनी एवं एंड्रयूज गंज से आने वाले ट्रैफिक को डिफेंस कॉलोनी मार्केट रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
सेकंड एवेन्यू रोड-जोर बाग क्रॉसिंग: खन्ना मार्केट एवं लोधी कॉलोनी से आने वाले ट्रैफिक को जोर बाग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

फोर्थ एवेन्यू रोड-जोर बाग क्रॉसिंग: सेवा नगर एवं जोर बाग से आने वाले ट्रैफिक को जोर बाग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
लाला लाजपत राय कट (CBI बिल्डिंग): मूलबंद से आने वाले ट्रैफिक को जेएलएन रोड की ओर बाएँ मुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे मथुरा रोड के रास्ते दिल्ली चिड़ियाघर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि प्रभावित रूट से बचें, यात्रा की पहले से प्लानिंग करें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या अस्पताल जाने वालों को अतिरिक्त समय रखें और जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।



सहारापुर, संवाददाता। जनपद में सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब सार्वजनिक सेवा से जुड़े वाहनों, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों तथा विशेष श्रेणी के माल परिवहन में लगे वाहनों में जीपीएस आधारित वाहन लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र और आपातकालीन सहायता बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

सहायक संचालक परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य वाहनों की निगरानी मजबूत करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बस, टैक्सी सहित अन्य व्यावसायिक वाहन, राष्ट्रीय परमिट से संचालित वाहन तथा विशेष श्रेणी के माल ढोने वाले वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे, जबकि दोपहिया, ई-रिक्शा, तिपहिया और बिना परमिट वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि एक जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत सभी संबंधित वाहनों में जीपीएस यंत्र और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। जिन वाहनों में यह उपकरण नहीं लगे होंगे, उनके पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र तथा अन्य परिवहन संबंधी कार्य नहीं किए जाएंगे।

वहीं आर आई रोहित कुमार ने प्रदूषण को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) भी नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी वाहन में मानक से अधिक प्रदूषण पाया जाता है या आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं, तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से सभी आवश्यक मानकों को पूरा करने और समय-समय पर जांच कराने की अपील की। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 15 कंपनियों को अधिकृत किया गया है। इनमें एकोलेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अटलांटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैकबॉक्स

जीपीएस टेक्नोलॉजीज, कंटेनर टेक्नोलॉजीज, डैनलॉ टेक्नोलॉजीज इंडिया, जीट्रोपीसिस्टम्स, इंटैगल्स लैब, लुमेक्स इटुरान टेलीमैटिक्स, निपॉन ऑडियोट्रोनिक्स, रोसमार्ट ऑटोटेक, रोडपॉइंट लिमिटेड, ट्रैकनाउ प्राइवेट लिमिटेड, आईट्रायंगल इन्फोटेक, पीएनवी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सर्विसेज तथा वाट्सयू एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

इन अधिकृत कंपनियों के माध्यम से ही निर्धारित मानक के उपकरण लगाए जाएंगे।

परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में शीघ्र जीपीएस यंत्र, पैनिक बटन तथा अन्य आवश्यक मानकों की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मजबूत किया जा सके।

दिल्ली की नई स्लम नीति: झुग्गियों में बनेंगे शापिंग कॉम्प्लेक्स और ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली सरकार नई स्लम पुनर्वास नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत झुग्गीवासियों को शापिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति में स्कूल और जन सुविधा केंद्र भी शामिल होंगे। यह नीति इस महीने अंतिम रूप लेगी। मौजूदा पात्रता अवधि 10 साल बढ़ाकर 2025 तक की जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार तैयार हो रही नई स्लम पुनर्वास नीति के तहत इन इलाकों में रहने वालों को शापिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एरिया और ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट जैसी सुविधाएं देने की योजना बना रही है।

सरकार की प्रस्तावित नीति के अनुसार जिन सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है उनमें स्कूल, जन सुविधा केंद्र आदि की व्यवस्था भी शामिल है। इस नीति की तैयारी अंतिम चरण में है और इस महीने इसे अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।

यहां बता दें कि सरकार मौजूदा नीति के तहत लाभार्थियों की पात्रता अवधि 1 जनवरी, 2015 से 10 साल बढ़ाकर 1 जनवरी, 2025 करने की भी योजना बना रही है, जिससे कई स्लम में रहने वाले लोग पक्के घर के लिए अधिकृत हो सकेंगे। दिल्ली में लगभग 750 स्लम क्लस्टर हैं।

आधी झुग्गियां केंद्र सरकार की एजेंसियों की जमीन पर
इनमें से लगभग आधी झुग्गियां रेलवे, भूमि एवं विकास विभाग (एलएनडीओ) और डीडीए जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों की जमीन पर हैं, जो उनके पुनर्वास के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती हैं। अन्य झुग्गी-झोपड़ियां दिल्ली सरकार की



जमीन पर हैं, जहां पुनर्वास की जिम्मेदारी दिल्ली के शहरी विकास विभाग के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) करता है।

अभी दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास का काम दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015 के तहत होता है, जो झुग्गियों को उसी जगह पर या झुग्गी वालों को पांच किलोमीटर के दायरे में दूसरी जगह देकर पुनर्वास को प्राथमिकता देती है।

झुग्गी वालों को अब तक आवास नहीं मिल सका
एक झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले को 25 वर्ग मीटर के घर के लिए 1.12 लाख रुपये और पांच साल के लिए रखरखाव के लिए 30,000 रुपये निर्धारित हैं। हालांकि इस नीति के तहत दिल्ली में एक भी झुग्गी वालों को अब तक आवास नहीं मिल सका है। यह नीति शुरू से ही विवादों में आ गई थी। जब उस समय की आप सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू न कर अपनी नीति

तैयार कर इसे लागू किया था, जिसे लेकर अड़गे ही लगे रहे। इसी कारण है 2008 से दिल्ली सरकार ने डूसिब और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) के जरिए, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिए द्वारका, सुल्तानपुरी, भलस्वा-जहांगीरपुरी, सावदा घेवरा, पृथु खुर्द और टिकरी कलां में बनाए गए 52,584 फ्लैट झुग्गी वालों को आवंटित नहीं हो पाए।

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित

विशेष लोक अदालत

इन सात कोर्ट परिसरों में

अप्रैल 05 2026

पटियाला हाउस

कड़कड़डूमा

तीस हज़ारी

साकेत

रोहिणी

द्वारका

राउज एवेन्यू

1. केवल दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित और 31.12.2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए झमझोता योग्य यातायात चालान/नोटिस ही इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।
2. नोटिस/चालान डाउनलोड करने और प्रिंटआउट लेने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर लॉग इन करें: <https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat> या व्हाट्सएप कोड स्कैन करें।
3. नोटिस/चालान का प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है। न्यायालय परिसर में प्रिंटआउट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

यह लिंक 30.03.2026 को सुबह 10:00 बजे से सक्रिय होगा और चालान/नोटिस की सीमा 2,00,000 समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा। प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड किए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए

ट्वें फॉलो करें: @delhitraffic @delhitraffic

24x7 यातायात हेल्पलाइन: 011-2584444/1095

व्हाट्सएप कोड -1 स्कैन करें: अनुरोधित अपॉइंटमेंट बुकिंग की प्रक्रिया

व्हाट्सएप कोड -2 स्कैन करें: नोटिस और चालान डाउनलोड करें

वेबसाइट: www.traffic.delhipolice.gov.in
ई-मेल: info.traffic@delhipolice.gov.in

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राउज एवेन्यू बिल्डिंग कोर्ट कम्प्लेक्स, तुलीय रस्त, पॉइंट नॉट टोवार्ड्स जयपुर मार्ग, नई दिल्ली-110002

हेल्पलाइन 1516

एक यातायात प्रदूरी बॉक्स
वाकवाक प्रवृत्ति एवं उन्नतता के लिए

एक यातायात प्रदूरी बॉक्स
वाकवाक प्रवृत्ति एवं उन्नतता के लिए

पुलिस प्रवृत्त, दिल्ली को ई-मेल करें: cpdelhi@delhipolice.gov.in | लिंक: www.delhipolice.gov.in | लिंक: पुलिस प्रवृत्त, दिल्ली को फॉर वॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर तुरंत पुलिस सहायता के लिए 112 नम्बर पर कॉल करें | पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 14547

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

आज का साइबर सुरक्षा विचार : भारत में साइबर अपराध मामलों के पंजीकरण में तेज वृद्धि



भारत में साइबर अपराध मामलों के पंजीकरण में तेज वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2026 में 86,420 मामले दर्ज किए, जो 2021 के 52,974 मामलों से कहीं अधिक है। यह वृद्धि वित्तीय धोखाधड़ी, रजिस्ट्रार गिरफ्तारी ठगी, फ्रिंशिंग और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से प्रेरित है। यह प्रवृत्ति बढ़ते साइबर खतरों और बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र दोनों को दर्शाती है।

प्रमुख आँकड़े
- साइबर अपराध मामले (NCRB 2026): 86,420
- 2021 से वृद्धि: ₹63% (52,974 मामलों से)
- सबसे अधिक शिकायत वाले राज्य: कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश
- मुख्य धोखाधड़ी प्रकार: वित्तीय ठगी, डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी, फ्रिंशिंग, ओटीपी धोखाधड़ी और प्रतिरूपण वृद्धि के पीछे कारण
1. डिजिटल अपनापन और ऑनलाइन लेन-देन
- UPI, ऑनलाइन बैंकिंग और ई-कॉमर्स के तेज विस्तार ने धोखाधड़ियों को अधिक अवसर दिए।
- "डिजिटल इंडिया" पहल से लाखों नए उपयोगकर्ता ऑनलाइन आए, जिनमें से कई साइबर



जगुरूकता से वंचित हैं।
2. वित्तीय ठगी और "डिजिटल गिरफ्तारी" धोखाधड़ी
- अपराधी पुलिस या सरकारी एजेंसियों का रूप धारण कर पीड़ितों से धन स्थानांतरित करवाते हैं।
- 2026 में यह भारत के सबसे बड़े साइबर खतरों में से एक बन गया है।
3. सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म
- नकली प्रोफाइल, रसेक्सटॉर्शनर और गलत सूचना अभियानों में वृद्धि।
- प्लेटफॉर्म पर आसन गुमनामी से पहचान और रोकथाम कठिन हो जाती है।
4. बेहतर रिपोर्टिंग और जागुरूकता
- NCRB और राज्य पुलिस ने साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन को मजबूत किया।
- जागुरूकता अभियानों और

मैलवेयर के विकास ने हमलों को और जटिल बना दिया है।
जोरिखम और चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागुरूकता की कमी के कारण अधूरा रिपोर्टिंग अभी भी मौजूद है।
- कानून प्रवर्तन क्षमता सीमित है, साइबर सेल को कौशल और जनशक्ति की कमी है।
वृद्धि वित्तीय नुकसान बढ़ रहे हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यवसायों को निशाना बनाया जा रहा है।
सिफरिंग
- हर जिले में प्रशिक्षित कर्मियों के साथ साइबर सेल को मजबूत करें।
- जन-जागुरूकता अभियान चलाएँ, विशेषकर UPI सुरक्षा, OTP धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी ठगी पर।
- बैंकों और टेलेकॉम प्रदाताओं के साथ सहयोग कर संदिग्ध लेन-देन और नंबरों को तुरंत ब्लॉक करें।
- स्कूलों और कार्यस्थलों में अनिवार्य साइबर स्वच्छता शिक्षा लागू करें।
- निष्कर्ष: भारत में साइबर अपराध पंजीकरण में वृद्धि डिजिटल धोखाधड़ी और बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र दोनों का परिणाम है। वित्तीय ठगी, डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी और फ्रिंशिंग प्रमुख हैं, जिनमें कर्नाटक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे शहरी राज्यों में शिकायतें सबसे अधिक हैं। यह प्रवृत्ति मजबूत साइबर पुलिसिंग, जागुरूकता अभियानों और प्रणालीगत सुधारों को तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

'डिजिटल इस्टबिन' बनते शरीर और मन को बचाने की चुनौती

उमेश कुमार साहू

हम इतिहास के उस कालखंड में जी रहे हैं जहाँ इंसान ने प्रकृति पर विजय तो पा ली है लेकिन खुद के शरीर से हार रहा है। आज हमारे पास 'स्मार्टवॉच' है जो दिल की धड़कन गिनती है पर हमारे पास उस दिल की बात सुनने का समय नहीं है। हम 5G की रफ्तार से डेटा तो डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन हमारा अपना 'इम्यून सिस्टम' (रोग प्रतिरोधक क्षमता) हर बदलते मौसम के साथ 'हैंग' हो जाता है। 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह पूछने का मौका है कि क्या हम वास्तव में 'जी' रहे हैं या सिर्फ 'सर्वाइव' कर रहे हैं?

1. स्वास्थ्य का आधुनिक अर्थ: होलिस्टिक वेलबीइंग
अक्सर हम समझते हैं कि अस्पताल न जाना ही स्वास्थ्य है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की परिभाषा अब और गहरी हो गई है। असली स्वास्थ्य का अर्थ है - शारीरिक क्षमता, मानसिक शांति और सामाजिक संतुलन का संगम।
नया नजरिया:
• यदि आप ज़िम में 100 किलो वजन उठा लेते हैं लेकिन घर आकर छोटी सी बात पर चिल्लाने लगते हैं तो आप अस्वस्थ हैं। सच्चा आरोग्य वह है जहाँ तन ऊर्जावान हो और मन शांत।
2. सोशल मीडिया और 'डोपामाइन' का जाल

आज की सबसे बड़ी बीमारी वायरस नहीं, बल्कि 'नोटिफिकेशन' है। हम सुबह उठते ही सूरज की पहली किरण के बजाय मोबाइल की नीली रोशनी (Blue Light) देखते हैं।
• दिक्कत: सोशल मीडिया पर दूसरों की 'परफेक्ट लाइफ' देखकर अपने सामान्य जीवन से नफरत करना 'मेंटल करप्शन' है। रील स्क्रॉल करते हुए घंटों बिताना हमारे मस्तिष्क के 'रिवॉइ सिस्टम' को खराब कर रहा है।
• समाधान: 'डिजिटल डिटॉक्स' को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। रात को सोने से 1 घंटे पहले और सुबह उठने के 1 घंटे बाद मोबाइल को 'नो एंट्री' जोन में रखें।
3. 'सिटिंग' (Sitting) है नया स्मोकिंग
विज्ञान कहता है कि लगातार घंटों तक कुर्सी या सोफे पर बैठना उतना ही जानलेवा है जितना कि सिगरेट पीना। हमारी मशीन यानी हमारा शरीर 'चलने' के लिए बना था, 'जमने' के लिए नहीं।
• बायो-हैकिंग: ऑफिस हो या घर, हर 40 मिनट पर 'स्टैंडिंग ब्रेक' लें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चुनें। याद रखें, शरीर फिट तो दिमाग भी 'हित' रहता है।
4. प्लेट का गणित: रकैलोरी नहीं, केमिकल गिनं
जैसा अन्न, वैसा मनन आज के अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड में सबसे बड़ी चेतनी है। हम 'फूड' नहीं, 'केमिकल' खा रहे हैं।

• भ्रम: डाइट सोडा या शुगर-फ्री लेबल आपको स्वस्थ नहीं बनाते। पैकेटबंद खाना 'स्तो पॉइजन' है।
• समाधान: अपनी थाली को 'रेनबो डाइट' (इंद्रधनुषी रंग) दें। ताजी सब्जियां, फल और मोटे अनाज को प्राथमिकता दें। जो खाना सोधे खेत से आया उसी तक आता है, वही असली 'सुपरफूड' है।
5. मानसिक स्वास्थ्य: रट्टीक दिखना, रट्टीक होना नहीं
हम अक्सर शारीरिक चोट पर पट्टी बांधते हैं, लेकिन मन के घावों को 'इग्नोर' करते हैं। स्ट्रेस, एंगजायटी और डिप्रेशन कोई टैबू नहीं, बल्कि इलाज योग्य बीमारियाँ हैं।
• जरूरी कदम: अकेलेपन को सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि वास्तविक रिश्तों से भरे। अपने मन की बात साझा करना दुनिया की सबसे बड़ी थैरेपी है। मेडिटेशन के 10 मिनट आपके दिमाग को 'रीव्यू' कर देते हैं।
6. स्लीप डेफिशिटेसी: नींद से समझौता यानी मौत से सौदा
नींद हमारे शरीर का 'रिपेयर सेंटर' है। जब हम सोते हैं, तो हमारा मस्तिष्क यादों को सहेजता है और शरीर विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालता है।
• खतरा: 7-8 घंटे की नींद की कमी हमारे इम्यून सिस्टम के 'सॉफ्टवेयर' को करंट कर देती है।



जिससे कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। नींद को विलासिता नहीं, निवेश समझें।
7. प्रिवेंटिव हेल्थकेयर: रचबाव इलाज से सस्ता है
हम गाड़ी की सर्विसिंग समय पर कराते हैं, लेकिन अपने शरीर की नहीं। 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार 'होल बॉडी चेकअप' अनिवार्य है।
• टीकाकरण और जांच: वैक्सिनेशन केवल

9. पर्यावरण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य
आप शुद्ध हवा बाजार से नहीं खरीद सकते। प्रदूषण आज की सबसे बड़ी 'साइलेंट किलर' बीमारी है। प्लास्टिक का कम उपयोग और अधिक से अधिक पेड़ लगाना अब 'सोशल वर्क' नहीं, बल्कि 'सेल्फ-डिफेंस' है। यदि प्रकृति स्वस्थ रहेगी, तभी हम सांस ले पाएंगे।
10. जागरूकता और संकल्प: My Health, My Right
इस वर्ष का संदेश स्पष्ट है - स्वास्थ्य आपका अधिकार है, लेकिन इसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी डॉक्टर आपको तब तक स्वस्थ नहीं रख सकता जब तक आप खुद इसके लिए तैयार न हों।
कल से नहीं, आज से!
स्वास्थ्य कोई 'डिस्टिनेशन' नहीं है जहाँ पहुँच कर आप रुक जाएं, यह एक निरंतर चलने वाली 'यात्रा' है। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक छोटा सा बदलाव करें - शायद एक फल ज्यादा खाना, शायद एक घंटा मोबाइल कम चलाना, या शायद सिर्फ 15 मिनट तेज चलना।
याद रखिये, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी 'सांसें' और 'धड़कनें' हैं। जब आप स्वस्थ होते हैं, तो आपके पास हजारों सपने होते हैं, लेकिन जब आप बीमार होते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक सपना होता है - स्वस्थ होना।

नाभि में छिपा है हर बीमारी का रामबाण इलाज

पिंकी कुंडू

- दिल कमजोर : नाभि में सरसों का तेल लगाओ, खून का दौरा तेज होगा।
- मर्दानगी खत्म : नाभि में बादाम का तेल लगाओ, शुक्राणु मजबूत होंगे।
- पीरियड में गड़बड़ : तिल का तेल लगाओ, दर्द गायब, हार्मोन बैलेंस
- डायबिटीज का कहर : तुलसी का डाय तेल लगाओ, ब्लड शुगर कंट्रोल
- कमर, घुटने दर्द : तिल का तेल लगाओ हड्डियां होंगी, लोहे जैसी मजबूत
- पेट में गैस : हींग का तेल लगाओ
- सिर दर्द, माइग्रेन :



बाजार में मिल रहे नकली दूधपेस्ट से सावधान रहें

हाल ही में दिल्ली में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी दूधपेस्ट जब्त किया, जो अवैध और अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा था। इन नकली उत्पादों को लोगों को धोखा देने के लिए प्रसिद्ध ब्रांडों के नाम से पैक करके बाजार में बेचा जा रहा था। प्रयोगशाला संबंधी अवलोकनों से यह संकेत मिलता है कि ऐसे नकली दूधपेस्ट में सोडियम लॉरिल सल्फेट (SLS) की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक हो सकती है, साथ ही कई अन्य अनियमित रसायन, कृत्रिम रंग तथा निम्न-स्तरीय सामग्री भी मिलाई जा सकती है। सही और मानक के अनुसार बनाए गए दूधपेस्ट में इन पदार्थों की मात्रा को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किंतु नकली उत्पादों में न तो गुणवत्ता का नियंत्रण होता है, न स्वच्छता का पालन और न ही किसी प्रकार की नियामक निगरानी। अत्यधिक मात्रा में कठोर रासायनिक डिटर्जेंट और अज्ञात रसायनों के संपर्क में आने से मसूड़ों में जलन, मुँह में छाले, मुख की कोमल ऊतकों को क्षति तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।



नकली व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों में अपरिष्कृत रसायनों की उपस्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि ये पदार्थ प्रतिदिन सीधे हमारे मुँह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह घटना इस बात की ओर भी संकेत करती है कि आज के समय में बाजार में नकली स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उत्पादों का प्रसार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। कुछ

* पैकेट पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और समाप्ति तिथि अवश्य जाँचें।
* जो उत्पाद असामान्य रूप से सस्ते या खराब छपाई वाले प्रतीत हों, उनसे बचें।
* यदि किसी दूधपेस्ट के उपयोग से जलन, असामान्य स्वाद या मुँह में तकलीफ हो, तो तुरंत उसका उपयोग बंद कर दें।
अच्छी मौखिक स्वच्छता समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम केवल प्रमाणित और विश्वसनीय दंत-स्वास्थ्य उत्पादों का ही उपयोग करें।
जनजागरूकता, कठोर नियामक कार्यवाही और जिम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार — ये तीनों मिलकर ही नकली उत्पादों के प्रसार को रोक सकते हैं और जनस्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।
याद रखें:
एक छोटा-सा दूधपेस्ट का ट्यूब भले ही सामान्य वस्तु लगे, परंतु जो चीज हम रोज अपने मुँह में उपयोग करते हैं, उसका हमारे दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
सतर्क रहें। जागरूक रहें। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें।

समर सूप – शरीर को टंडक देने वाला अमृत!

पिंकी कुंडू

गर्मी का सूप घमौरियों, थकान और गर्मी से होने वाली शरीर की गर्मी को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। यह न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को प्राकृतिक टंडक भी देता है।
सामग्री:
* बेसन - 1 कटोरी
* छाछ - 2 कटोरी (थोड़ा खट्टा हो तो बेहतर)
* पानी - 3-4 कटोरी
* जीरा पाउडर - 1 छोटा चम्मच

* लहसुन - 4-5 कलियाँ (कुटी हुई)
* नमक - स्वादानुसार
* धनिया - थोड़ा सा
रेसिपी (आसान तरीका):
1. बेसन को पानी में मिलाकर 3-4 घंटे (या रात भर) के लिए फरमेंट होने दें,
2. पानी उबालें और उसमें लहसुन और नमक डालें,
3. उसमें आटे का मिक्सचर डालें और लगातार चलाते रहें,
4. गाढ़ा होने पर टंडा होने दें,

5. फिर छाछ, जीरा पाउडर, धनिया डालकर मिलाएं
फायदे:
1. शरीर को नेचुरल टंडक
2. पाचन में सुधार
3. पाचन को ठीक रखता है शरीर हाइड्रेटेड रहता है
4. थकान कम करता है और एनर्जी देता है
कब लें? - सुबह या लंच से पहले
हेल्दी रहने के लिए आज ही सही आदतें अपनाएं!

आपका शरीर जो कुछ भी करता है, वह हमेशा अच्छा होता है

म्यूकस → टॉक्सिन को फंसाना।
बुखार → पैथोजन्स को मारना।
ट्यूमर → टॉक्सिन/पैथोजन्स के लिए जेल।
खांसी आपके एयरवे को साफ करना।
सूजन → इम्यून सेल्स को ठीक करने के लिए पानी भरना।
डायरिया → टॉक्सिन और पैथोजन्स को बाहर निकालना।
दर्द → आपको और नुकसान से बचाना।
थकान → आराम करने के लिए मजबूर करना ताकि आपका शरीर लड़ सके।
वायरस → कचरे के थैले जो सेल्स से टॉक्सिन बाहर निकालते हैं।
क्रेविंग → न्यूट्रिएंट्स की जरूरतों का मैसेज देना, नैतिक नाकामियों का नहीं।
कोलेस्ट्रॉल → एक्सक्रेशन के लिए टॉक्सिन से जुड़ता है, सेल्स को रिपेयर करता है।
वजन बढ़ना → जो आपका शरीर सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकाल सकता उसे स्टोर करना।
ब्रेन फोग → एक संकेत कि आपका शरीर बहुत ज्यादा काम कर



रहा है और एनर्जी को दूसरी जगह भेज रहा है।
स्किन ब्रेकआउट → जब लिवर ओवरलोड हो तो स्किन के जरिए डिटॉक्स करना।
लिम्फ नोड में सूजन → जो आपका शरीर नहीं चाहता उसे फालने

से रोकना और गहरी रुकावटों को रोकना।
हाइपोथायरायड → आपके एंड्रिनल ग्लैंड चीख रहे हैं, इसलिए आपका थायराइड बंद हो जाता है।
कब्ज → आपको अपच या टॉक्सिन से बचाने के लिए रुकना।
डिप्रेशन → ऐसे माहौल से दूर हो जाना जो आपको पोषण नहीं दे रहा है।
सूजन → टॉक्सिन को साफ करना और इन्फ्लेमेटेड टिशू को ठीक करना।
ऑटोइम्यूनटी → आपके लीकी गट से इन्फ्लेमेटेड सेल्स को साफ करना।
फंगस → टॉक्सिन को आपके ब्लडस्ट्रीम में जाने से पहले एब्जॉर्ब करना।
एच. पाइलॉरी → आपके पेट का कम एसिड जो खाना नहीं पचा सकता, उसे और कौन पचाएगा?
पैरासाइट्स → जो आप प्रोसेस नहीं कर सकते उसे खाना: टॉक्सिन्स, फूड, केमिकल के बचे हुए हिस्से, बिना पचा खाना, बायोफिल्म्स, वेस्ट, शुगर। साथ ही योस्ट, बैक्टीरिया को बैलेंस करना, शायद ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स को शांत करना।

जनस्वास्थ्य जागरूकता लेख : नकली दवाइयों, कॉस्मेटिक्स और प्रोटीन पाउडर के छिपे हुए खतरे

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों से कई चिंताजनक घटनाएँ सामने आई हैं, जिनसे यह पता चलता है कि बाजार में नकली दवाइयों, मिलावटी कॉस्मेटिक्स और नकली प्रोटीन पाउडर भी उपलब्ध हो सकते हैं। ये अवैध उत्पाद अक्सर अनियंत्रित और अस्वच्छ वातावरण में तैयार किए जाते हैं और लोगों को धोखा देने के लिए प्रसिद्ध ब्रांडों के नाम से बाजार में बेचे जाते हैं। ऐसे नकली उत्पादों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। नकली दवाइयों में गलत तत्व, बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में दवा, या कभी-कभी बिल्कुल भी सक्रिय औषधीय तत्व नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप संक्रमण, हृदय रोग, मधुमेह या अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को सही उपचार नहीं मिल पाता, जिससे उनकी बीमारी और गंभीर हो सकती है तथा कई बार जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार नकली कॉस्मेटिक्स और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में हानिकारक रसायन, विषैले रंग, भारी धातुएँ या निम्न गुणवत्ता के औद्योगिक पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। क्योंकि ये उत्पाद सीधे त्वचा, बालों या मुँह पर उपयोग किए जाते हैं, इसलिए वे एलर्जी, त्वचा को नुकसान, हार्मोनल असंतुलन और दीर्घकालिक विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकते हैं। एक और तेजी से बढ़ती चिंता नकली प्रोटीन पाउडर और पोषण सप्लीमेंट्स की उपलब्धता है। आजकल फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग के बढ़ते प्रचलन के कारण इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश, कुछ अनैतिक निर्माता इस मांग का फायदा उठाकर स्टार्च, आटा, कृत्रिम फ्लेवर या अन्य सस्ते और कभी-कभी हानिकारक पदार्थों से भरे नकली सप्लीमेंट्स को असली प्रोटीन के नाम पर बेच देते हैं। ऐसे मिलावटी सप्लीमेंट्स का नियमित सेवन किडनी पर दबाव, लिवर को नुकसान, मेटाबॉलिक विकार और पोषण



एक और तेजी से बढ़ती चिंता नकली प्रोटीन पाउडर और पोषण सप्लीमेंट्स की उपलब्धता है। आजकल फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग के बढ़ते प्रचलन के कारण इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश, कुछ अनैतिक निर्माता इस मांग का फायदा उठाकर स्टार्च, आटा, कृत्रिम फ्लेवर या अन्य सस्ते और कभी-कभी हानिकारक पदार्थों से भरे नकली सप्लीमेंट्स को असली प्रोटीन के नाम पर बेच देते हैं।

असंतुलन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकता है। ये घटनाएँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों का बाजार पूरी तरह धोखाधड़ी और अनैतिक गतिविधियों से मुक्त नहीं है। कुछ आपराधिक नेटवर्क प्रसिद्ध ब्रांडों की नकल करके कम कीमत पर नकली उत्पाद बेचते हैं और उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। उचित जागरूकता के अभाव में कई उपभोक्ता अनजाने में ही गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में आ जाते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए :
* दवाइयों हमेशा लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या अधिकृत फार्मसी से ही खरीदें।
* कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट्स केवल विश्वसनीय और प्रतिष्ठित विक्रेताओं से ही खरीदें।
* पैकेट पर निर्माता का नाम, बैच नंबर, पैकेजिंग की गुणवत्ता और समाप्ति तिथि अवश्य जाँचें।
* जो उत्पाद असामान्य रूप से सस्ते या सफ़ेद प्रतीत हों, उनसे बचें।
* यदि किसी उत्पाद के उपयोग से अचानक कोई दुष्प्रभाव या असुविधा महसूस हो, तो उसका उपयोग तुरंत बंद कर दें और योग्य चिकित्सक से परामर्श लें।
नकली स्वास्थ्य उत्पादों के प्रसार को रोकने के लिए कड़े नियामक नियंत्रण, सख्त गुणवत्ता परीक्षण और सतर्क कानून-



5 अप्रैल को रखा जाएगा वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जाने पूरी विधि और महत्व

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि 5 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने का भी विधान है।

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से पूजन करने से जीवन के कठिन से कठिन संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि 5 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा-

अर्चना की जाती है। साथ ही संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने का भी विधान है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर महीने में आने वाली संकष्टी और विनायक गणेश चतुर्थी को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने रखा जाता है, लेकिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व होता है, जिसे विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी कृपा शुभ-मांगलिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर करती हैं। साथ ही व्यक्ति को

सफलता भी मिलती है। लेकिन गणेश जी का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद प्रभावशाली माना जाता है। पंचांग के अनुसार, हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, जिससे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यही नहीं साधक को कठिन परिस्थितियों से मुक्ति भी प्राप्त होती है।

शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11:59 मिनट पर होगा। चतुर्थी तिथि का समापन 6 अप्रैल को दोपहर 2:10 मिनट पर होगा। उदयतिथि और चंद्रोदय के मुताबिक, 5 अप्रैल 2026 को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा।

चंद्रोदय का समय
विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:54 मिनट पर रहेगा। आपको बता दें कि संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण चंद्रोदय के समय ही



किया जाता है।
विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत महत्व
भगवान गणेश के अष्टविनायक रूपों में से एक

विकट रूप भी है। समस्त प्रकार के ज्ञात-अज्ञात भय, रोग, शोक एवं दुर्घटनाओं से मुक्ति हेतु भगवान विकट की पूजा की जाती है। भगवान विकट अपने

भक्तों को अपराजेयता एवं निर्भयता प्रदान करते हैं और घोर से घोर महासंकटों में भक्तों की रक्षा करते हैं।

चारधाम मार्ग पर अब रात 10 बजे के बाद थमेगा पहियों का शोर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए बदले नियम



उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने नए और सख्त गाइडलाइंस लागू किए हैं। पहाड़ी रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब वाहनों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है।
क्या है नए नियम ?
रात्रि प्रतिबंध: यात्रा मार्गों पर रात 10:00 बजे से सुबह 04:00 बजे के बीच वाहनों के चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। कुछ विशेष संवेदनशील मार्गों पर यह प्रतिबंध शाम 08:00 बजे से भी लागू हो सकता है।
ग्रीन कार्ड अनिवार्य: किसी भी व्यावसायिक वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के त्रिभुज के आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। यह कार्ड वाहन की फिटनेस और

डाइवर के दस्तावेजों की जांच के बाद ही जारी किया जा रहा है।
ट्रैकिंग और जीपीएस: सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए मोबाइल जीपीएस के जरिए वाहनों को लोकेशन ट्रैक करेगी ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।
क्यों लिया गया यह फैसला ?
दुर्घटनाओं पर लगाम: रात के समय पहाड़ों पर Visibility कम हो जाती है और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है।
डाइवरों को आराम: लगातार डाइविंग से होने वाली थकान के कारण होने वाले हादसों को कम करने के लिए यह अनिवार्य विश्राम समय तय किया गया है।
जाम से मुक्ति: सुबह-सुबह ट्रैफिक को व्यवस्थित तरीके से छोड़ने के लिए

चेक पोस्ट पर भीड़ को नियंत्रित करना आसान होगा।
इन बसों के प्रवेश पर रहेगी रोक
ऐसी बसें जिनकी चौड़ाई 2570 मिलीमीटर से ज्यादा है या जिनका व्हील बेस (पहियों के बीच की दूरी) 4500 मिलीमीटर से अधिक है, उन्हें पहाड़ी मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन मानकों से बड़े वाहनों को हरिद्वार या ऋषिकेश के पार्किंग स्थलों पर ही रोक दिया जाएगा। बड़े वाहनों से आने वाले यात्रियों को ऋषिकेश से छोटी बसों या टैक्सियों के माध्यम से आगे की यात्रा पूरी करनी होगी।
डाइवरों के लिए अनिवार्य कोड ऑफ कंडक्ट
ड्रेस कोड और सुरक्षा: वाहन चलाते समय चालक के लिए जूते पहनना

अनिवार्य है (चप्पल या सैंडल पहनकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी)।
स्वास्थ्य परीक्षण: केवल उन्हीं चालकों को स्टेयरिंग संचालन दिया जाएगा जिनके पास वैध मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा।
मार्ग का ज्ञान (Training): मैदानी इलाकों या अन्य राज्यों से आने वाले बाहरी चालकों को सीधे पहाड़ों पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उन्हें पहले पहाड़ी रास्तों का विशेष प्रशिक्षण (Route Orientation) लेना होगा।
अनुभव को प्राथमिकता: यात्रा मार्ग पर केवल उन्हीं डाइवरों को अनुमति दी जाएगी जिनके पास पहाड़ी ढलानों और घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाने का पर्याप्त अनुभव है।

अब नए समय पर होंगे बाबा श्याम के दर्शन, गर्मी को देखते हुए आरती के समय में हुआ बदलाव



राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है। अप्रैल महीने की शुरुआत और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर बाबा श्याम की विभिन्न आरतियों के समय को संशोधित किया गया है।
राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है। अप्रैल महीने की शुरुआत और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर बाबा श्याम की विभिन्न आरतियों के समय को संशोधित किया गया है। अब श्रद्धालु बदले हुए समय के अनुसार ही मंदिर में हाजिरी लगा पाएंगे।
आरती का नया समय

(Summer Schedule 2026)
मंदिर प्रशासन के अनुसार, गर्मियों के इस शेड्यूल में सुबह की आरती को जल्दी और रात की आरती को थोड़ा देरी से तय किया गया है:
मंगला आरती: बाबा श्याम की पहली आरती अब तड़के सुबह 04:30 बजे होगी।
शुंभार आरती: बाबा का भव्य शुंभार देखने के लिए अब भक्तों को सुबह 07:15 बजे (कुछ विशेष दिनों में 07:30 बजे) मौजूद रहना होगा।
भोग आरती: दोपहर के समय लगने वाला विशेष भोग अब 12:30 बजे लगाया जाएगा।
संध्या आरती: शाम की आरती का समय बदलकर अब 07:15 से 07:30

बजे के बीच कर दिया गया है।
शयन आरती: रात को बाबा को विश्राम कराने वाली शयन आरती अब रात्रि 10:00 बजे संपन्न होगी।
दर्शन प्रेमियों के लिए विशेष सूचना
गर्मियों के दौरान मंदिर के कपाट दोपहर में कुछ समय के लिए विश्राम हेतु बंद किए जाते हैं।
सुबह के दर्शन: 04:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
शाम के दर्शन: शाम 04:00 बजे से रात 10:00 बजे तक।
एकादशी और विशेष उत्सवों के मौके पर मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में भक्तों को इसी नए समय का पालन करना होगा।

बांके बिहारी मंदिर में समिति और सेवायत के बीच बड़ा विवाद, जानें क्यों इस बार नहीं सजा फूल बंगला

चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होने वाला विश्व प्रसिद्ध 'फूल बंगला' उत्सव इस बार विवादों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है।

चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होने वाला विश्व प्रसिद्ध 'फूल बंगला' उत्सव इस बार विवादों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मंदिर की हाई-पावर मैनेजमेंट कमेटी और सेवायत गोस्वामियों के बीच ठनी रार ने करोड़ों भक्तों को मायूस कर दिया है।

विवाद की असली जड़: 15 हजार बनाम 1.51 लाख
इस साल विवाद का मुख्य कारण फूल बंगला सजाने के लिए तय की गई सहयोग राशि है। मंदिर प्रबंधन समिति ने इस वर्ष फूल बंगला सजाने के लिए रसीद की राशि को सीधे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1.51 लाख रुपये कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि सेवायत भक्तों से लाखों रुपये लेते हैं, जबकि मंदिर कोष में मात्र 15 हजार रुपये जमा होते हैं।
मंदिर के विकास और व्यवस्थाओं के लिए इस राशि को बढ़ाना जरूरी है। सेवायत गोस्वामियों का तर्क है कि यह वृद्धि बहुत अधिक है और सदियों से चली आ रही परंपरा में प्रशासनिक



दखलअंदाजी है। उनका कहना है कि इतनी मोटी रकम हर कोई वहन नहीं कर सकता, जिससे यह सेवा केवल अमीरों तक सीमित रह जाएगी।
परंपरा पर पड़ा असर
आमतौर पर 29 मार्च से बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगलों का सजना शुरू हो जाता है, जो अगले 137 दिनों तक चलता है। लेकिन इस बार नियमों की सख्ती और फीस वृद्धि के विरोध में कई सेवायतों ने बुकिंग लेने से हाथ धोने का फैसला किया है।
एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप
मंदिर परिसर में इस समय तनाव का माहौल है। जहाँ एक ओर

प्रबंधन समिति पारदर्शिता और मंदिर की आय बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं सेवायत इसे अपने धार्मिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर "ठीकरा फोड़" रहे हैं:
सेवायत: "समिति के तानाशाही रवैयें के कारण उत्सव की गरिमा खत्म हो रही है।"
समिति: "सेवायत पारदर्शिता नहीं चाहते और निजी स्वार्थ के लिए परंपरा को रोक रहे हैं।"
भक्तों की बड़ी मायूसी
दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु, जो भीषण गर्मी में ठाकुर जी को फूलों के शीतल बंगले में विराजमान देखने आते हैं, वे इस खोजतान से सबसे ज्यादा दुखी हैं। वृंदावन आने वाले पर्यटकों की संख्या पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है।

घर में कंगाली आने से पहले मिलते हैं ये संकेत, समय रहते पहचानें वरना बढ़ सकती है आर्थिक परेशानियां

वास्तु शास्त्र को भारतीय परंपरा में जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने वाला महत्वपूर्ण विज्ञान माना गया है। इसमें घर, दिशा, ऊर्जा और दैनिक आदतों से जुड़े ऐसे नियम बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। वास्तु के अनुसार, जब किसी व्यक्ति या परिवार पर आर्थिक संकट आने वाला होता है, तो उससे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

वास्तु शास्त्र को भारतीय परंपरा में जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने वाला महत्वपूर्ण विज्ञान माना गया है। इसमें घर, दिशा, ऊर्जा और दैनिक आदतों से जुड़े ऐसे नियम बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। वास्तु के अनुसार, जब किसी व्यक्ति या परिवार पर आर्थिक संकट आने वाला होता है, तो उससे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।



यदि घर में शीशा, ग्लास या अन्य कांच की चीजें बार-बार टूटने लगे, तो यह नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत है। यह स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है।
परिवार में लगातार झगड़े होना
वास्तु के अनुसार, जिस घर में बार-बार बिना कारण झगड़े होते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसका सीधा असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और धीरे-धीरे धन की कमी होने लगती है।
आभूषणों का बार-बार खो जाना
यदि घर में सोने या चांदी के आभूषण बार-बार

खोने लगे, तो इसे भी आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं है।
पैसे का हाथ में न टिकना
कई बार लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता। वास्तु के अनुसार, यह भी आर्थिक अस्थिरता और आने वाली कंगाली का संकेत हो सकता है।
घर में लाल चींटियों का दिखना घर में लाल चींटियों का अचानक बढ़ जाना भी शुभ नहीं माना जाता। यह संकेत देता है कि आर्थिक संकट से बचा जा सकता है और घर में सुख-समृद्धि बनाए रखी जा सकती है।

घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। टूटे हुए सामान को तुरंत हटा दें। जल से संबंधित लीकज तुरंत ठीक करवाएं। रोजाना पूजा-पाठ और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें।
तुलसी के पौधे की नियमित देखभाल करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रकृति और घर का वातावरण हमें पहले ही संकेत दे देता है कि आगे क्या होने वाला है। जरूरत है उन संकेतों को समझने और समय रहते सही कदम उठाने की। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो बड़े आर्थिक संकट से बचा जा सकता है और घर में सुख-समृद्धि बनाए रखी जा सकती है।

खातीवास-खेड़ी गांवों से मेरा पारिवारिक रिश्ता : आरती सिंह राव

हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने गांव खातीवास में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

सरकार ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध - बोली स्वास्थ्य मंत्री खातीवास व खेड़ी गांवों के विकास के लिए दस-दस लाख रुपए देने की घोषणा

झज्जर, 4 अप्रैल। हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध है। प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को मूल रूप दिया जा रहा है। खेड़ी व खातीवास गांव उनके अपने गांव हैं दोनों गांवों से उनका पारिवारिक रिश्ता है, जब भी मदद की जरूरत पड़ी, यहां के लोगों ने दिल खोलकर मदद की है, दोनों गांवों के विकास के मामले कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने खातीवास व खेड़ी गांवों के विकास के लिए दस-दस लाख रुपए देने की घोषणा की।

कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव शनिवार को निकटवर्ती गांव खातीवास में दादा सिराज वाला मंदिर में आयोजित अभिनंदन समारोह में ग्रामीण सभा को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का ग्राम पंचायत ने फूल मालाओं व पुष्पहार से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खेड़ी खातीवास गांवों के ग्रामीणों ने जो मान सम्मान दिया है वे कभी नहीं भूल पाएंगी। चूंकि इन गांवों से मेरा वर्षों पुराना पारिवारिक जुड़ाव भी है। आप सभी के सहयोग व आशीर्वाद से मुझे अटेली से विधायक और राज्य सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है।

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने विकास के मामले में इस क्षेत्र की निरन्तर अनदेखी की। लेकिन वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों को निरन्तर बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की सोच है कि प्रदेश में एक समान विकास



को बढ़ावा दिया जाए, जिसके चलते सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत खेड़ी व खातीवास की तरफ से जो मांग पत्र मिला है, उनमें अधिकांश मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पानी निकासी के लिए जो पाइप लाइन का काम है, उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि

उन्हें इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। क्षेत्र के लोग किसी भी जनहित के कार्यों को लेकर उनसे कभी भी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में सरकार की तरफ से एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि मशीनों और एक्सपर्ट स्टाफ लगाया गया है। आयुष्मान योजना के तहत भी लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकार सभी क्षेत्रों और वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में



स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को बेहतर इलाज, दवाइयों की उपलब्धता और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यह सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका आमजन को पूरा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने आमजन से सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बिधाना ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार अतिमंजूर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए जिला परिषद झज्जर भी पूरा सहयोग करेगी।

भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मिकी ने कैबिनेट मंत्री का झज्जर पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने आमजन से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए



प्रेरित किया। समारोह में यह गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद

इस अवसर पर गांव खातीवास सरपंच सुशीला देवी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोमवती जाखड़, अमित जून, समाजसेवी रमेश कुमार, संस्कारम गुप के चेयरमैन डॉ महिपाल यादव, पूर्व कुलपति जेपी यादव, रेवाड़ी जिला परिषद के चेयरमैन मनोज यादव, अनिल रायपुर, विकास बडखोदा, झज्जर यादव महासभा के अध्यक्ष रामौतार यादव, मार्किट कमेटी

झज्जर के चेयरमैन सतबीर यादव, अजय पटौदा, जहाजगढ़ के सरपंच प्रतिनिधि उदय सिंह, पलड़ा के सरपंच रामनिवास, एक्स सर्विस मेन लीग के जिला अध्यक्ष सुवेदार सुरेंद्र सिंह यादव के अलावा जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसीपी शम्भेर सिंह, दिनेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान, आयुष अधिकारी डॉ. पवन देशवाल, डॉ. बिजेंद्र गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना: श्री हजूर साहिब नांदेड़ की निःशुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक करें सरल पोर्टल पर पंजीकरण

परिवहन विशेष न्यून

— संगत के दर्शन के लिए होगी विशेष ट्रेन संचालित

झज्जर, 04 अप्रैल। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे।

डीसी स्विन्दर रविन्द्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। पात्र व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने

स्मार्ट फोन से सरल हरियाणा पोर्टल पर घर बैठे इस निःशुल्क यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

योजना का लाभ उठाने के लिए यह होगी पात्रता

डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी हो और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा आवश्यक है, इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक के रूप में पूर्ण भुगतान पर साथ

ले जाने की अनुमति है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।

पंजीकरण के उपरांत संगत को डीआईपीआरओ कार्यालय में देनी होगी सूचना

डीसी ने बताया कि आवेदन करने के उपरांत आवेदक को लघु सचिवालय, झज्जर स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अवश्य देनी होगी ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना रेलवे को समय पर भेजी जा सके। पंजीकृत व्यक्ति 16 अप्रैल से पहले यह सूचना डीआईपीआरओ कार्यालय में अवश्य दें।



गांवों में पहली बार जनता देख रही है अपना पैसा, अपना विकास

[ईग्रामस्वराज: गांवों को इंतजार नहीं, अधिकार देने वाली व्यवस्था] [जब गांवों तक पहुंचा डिजिटल शासन, तब बदला विकास का अर्थ]

जब किसी देश के गांव बदलते हैं, तभी उसका भविष्य बदलता है। आज भारत के गांवों में ऐसा ही ऐतिहासिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कभी पंचायत कार्यालयों में धूल खाती फाइलें, महीनों तक रुके भुगतान और विकास योजनाओं पर उठते सवाल आम थे। लेकिन अब वही ग्राम पंचायतों डिजिटल व्यवस्था के बल पर नई पहचान बना रही हैं। ईग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से ₹3 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान होना केवल सरकारी उपलब्धि नहीं, बल्कि गांवों में बदलती व्यवस्था का मजबूत प्रमाण है। यह सफलता बताती है कि अब विकास का धन कागजों में नहीं अटकता, बल्कि सीधे जरूरत और काम तक पहुंचता है। भारत के गांव अब केवल विकास की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं विकास की दिशा तय कर रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव ने पंचायतों के कामकाज का पूरा स्वरूप बदल दिया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित ईग्रामस्वराज पोर्टल, ई-पंचायत अभियान का एकिकृत मंच है, जहां योजना, बजट, लेखा, निगरानी और भुगतान की पूरी प्रक्रिया एक साथ पूरी होती है। पहले ग्राम पंचायतों को अलग-अलग रजिस्टर, विभागीय मंजूरी और कागजी कार्यवाही पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे समय अधिक लगता था और गड़बड़ की आशंका भी बनी रहती थी। अब पंचायतें गांव की जरूरत के अनुसार योजना बनाती हैं, उसे पोर्टल पर दर्ज करती हैं और काम पूरा होते ही भुगतान जारी



कर देती हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली से जुड़ाव के कारण हर लेन-देन तुरंत दर्ज होता है और उसका पूरा विवरण सुरक्षित रहता है।

जहां कभी गांवों में विकास योजनाएं कागजों तक सीमित रहती थीं, वहीं आज वही गांव डिजिटल बदलाव की मिसाल बन रहे हैं। मार्च 2026 तक ईग्रामस्वराज पोर्टल से ₹3 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही ₹53,342 करोड़ का हस्तांतरण हुआ। यह बताता है कि गांवों ने डिजिटल व्यवस्था को तेजी से अपनाया है। आज 2,59,798 पंचायतों राज संस्थाएं और 1.60 करोड़ से अधिक विक्रेता इस मंच से जुड़े हैं। साथ ही 2,55,254 ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं पोर्टल पर अपलोड कर चुकी हैं। इतनी बड़ी भागीदारी सिद्ध करती है कि ग्रामीण भारत अब तकनीक से दूर नहीं, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ रहा है। गांवों की चौपाल है कि गांवों में भवन तक अब डिजिटल सौच पहुंच चुकी है।

जहां पहले पंचायतों के खर्च और योजनाएं लोगों से छिपी रहती थीं, वहीं अब हर जानकारी सबके सामने है। यही इस

व्यवस्था को सबसे बड़ी ताकत है— पारदर्शिता और जवाबदेही। पहले गांवों में यह जानना कठिन था कि पंचायत को कितनी राशि मिली और वह कहाँ खर्च हुई। योजनाओं की जानकारी अक्सर कुछ लोगों तक सीमित रहती थी। अब ईग्रामस्वराज पोर्टल पर हर पंचायत का पूरा हिसाब उपलब्ध है। कोई भी नागरिक देख सकता है कि किस योजना के लिए कितनी राशि मिली, चुका है। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही ₹53,342 करोड़ का हस्तांतरण हुआ। यह बताता है कि गांवों ने डिजिटल व्यवस्था को तेजी से अपनाया है। आज 2,59,798 पंचायतों राज संस्थाएं और 1.60 करोड़ से अधिक विक्रेता इस मंच से जुड़े हैं। साथ ही 2,55,254 ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं पोर्टल पर अपलोड कर चुकी हैं। इतनी बड़ी भागीदारी सिद्ध करती है कि ग्रामीण भारत अब तकनीक से दूर नहीं, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ रहा है। गांवों की चौपाल है कि गांवों में भवन तक अब डिजिटल सौच पहुंच चुकी है।

सबसे बड़ा बदलाव गांव की अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है। पहले छोटे दुकानदारों, स्थानीय ठेकेदारों और सेवा देने वालों को भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार उन्हें पंचायत कार्यालय के बाहर चक्कर लगाने पड़ते थे। अब भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। इससे विचलियों की भूमिका लोगभग समाप्त हो गई है। समय पर धन

जनभागीदारी का नया आधार बन गया है। यह सफलता जितनी बड़ी है, उसका सफर उतना ही कठिन रहा है। देश के अनेक दूरस्थ गांवों में इंटरनेट की कमी, अनियमित बिजली और डिजिटल जानकारी का अभाव बड़ी बाधाएं थीं। शुरुआत में कई पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी नई व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन लगातार प्रशिक्षण और सरल प्रणाली ने यह मुश्किल दूर कर दी। पंचायत प्रतिनिधियों को तकनीकी प्रशिक्षण मिला, गांवों तक डिजिटल उपकरण पहुंचे और पोर्टल को इतना आसान बनाया गया कि कम पढ़े-लिखे लोग भी इसका उपयोग कर सकें। यही कारण है कि आज 2.5 लाख से अधिक पंचायतें इस मंच से जुड़ चुकी हैं। यह साबित करता है कि मजबूत संकल्प के सामने हर बाधा छोटी पड़ जाती है।

आज ईग्रामस्वराज पोर्टल गांवों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यह केवल एक वेबसाइट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। आने वाले समय में सरकारी ई-बाजार से जुड़ाव, तात्कालिक विवरण पट और उन्नत निगरानी जैसी सुविधाएं इसे और प्रभावी बनाएंगी। इससे पंचायतों के कामकाज में अधिक तेजी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल शासन अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी, तभी देश सशक्त होगा। और जब हर नागरिक अपनी पंचायत के कामकाज पर नजर रखेगा, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज स्थापित होगा—ऐसा स्वराज जो पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के हाथों में हो।

मिलने से छोटे व्यवसायियों का भरोसा बढ़ा है और गांवों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, विद्यालय मरम्मत और प्रशिक्षण और सरल प्रणाली ने यह मुश्किल दूर कर दी। पंचायत प्रतिनिधियों को तकनीकी प्रशिक्षण मिला, गांवों तक डिजिटल उपकरण पहुंचे और पोर्टल को इतना आसान बनाया गया कि कम पढ़े-लिखे लोग भी इसका उपयोग कर सकें। यही कारण है कि आज 2.5 लाख से अधिक पंचायतें इस मंच से जुड़ चुकी हैं। यह साबित करता है कि मजबूत संकल्प के सामने हर बाधा छोटी पड़ जाती है।

आज ईग्रामस्वराज पोर्टल गांवों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यह केवल एक वेबसाइट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। आने वाले समय में सरकारी ई-बाजार से जुड़ाव, तात्कालिक विवरण पट और उन्नत निगरानी जैसी सुविधाएं इसे और प्रभावी बनाएंगी। इससे पंचायतों के कामकाज में अधिक तेजी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल शासन अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी, तभी देश सशक्त होगा। और जब हर नागरिक अपनी पंचायत के कामकाज पर नजर रखेगा, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज स्थापित होगा—ऐसा स्वराज जो पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के हाथों में हो।

प्रो. आरके जैन "अरिजीव"

ग्राम स्तरीय मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित गांवों में 6 अप्रैल से लगेंगे जागरूकता शिविर



सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने दी जानकारी

झज्जर, 04 अप्रैल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर द्वारा ग्राम स्तरीय सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यस्थता अभियान 2.0 के अंतर्गत विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान एमडीडी ऑफ इंडिया एनजीओ, झज्जर के सहयोग से संचालित किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आपसी विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से कराना तथा आमजन को त्वरित, सुलभ एवं फिफायती न्याय के प्रति जागरूक करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने आमजन से अपील की है कि वे इन शिविरों में अधिक से अधिक भाग लें तथा मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराएं।

उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर्स एवं सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शोइयूल अनुरूप जागरूकता निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

यह रहेगा कार्यक्रमों का शोइयूल
06 अप्रैल - झज्जर शहर - शिवधन एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
07 अप्रैल - जहाजगढ़ एवं दूबलधन - नवीन कुमारी एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
09 अप्रैल - गांव बाकरा एवं मांगावास - शिवधन एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
13 अप्रैल - गोरिया एवं बहु शोलरी - बबीता कुमारी एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
16 अप्रैल - सुबाना एवं हसनपुर - रोशनी एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
18 अप्रैल - बहादुरगढ़ शहर - नेहा रानी एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
20 अप्रैल - डीहल एवं शेरिया - शिवधन एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
21 अप्रैल - मलिकपुर एवं गोधडी - शिवधन एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)
25 अप्रैल - बहादुरगढ़ शहर - नेहा रानी एवं संदीप जांगड़ा (सीएसडब्ल्यू)

नौकरीपेशा महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियों के साथ जीवन की दौड़



डॉ. विजय गर्ग



नौकरीपेशा महिला की सुबह ज्यादातर दूसरों से पहले शुरू होती है। घर के सभी काम, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और फिर समय पर कार्यालय पहुंचना यह सब एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। ऑफिस में भी उन्हें अपना काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना पड़ता है। दिन भर की थकान के बाद भी वे घर आकर दोबारा घरेलू कार्यों में शामिल हो जाती हैं।

आज के आधुनिक समाज में नौकरीपेशा महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। वे न केवल घर का रखरखाव करती हैं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवार बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन इस योगदान के साथ उन्हें दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ता है। एक तरफ कार्यालय की ड्यूटी और दूसरी तरफ घर की देखभाल। नौकरीपेशा महिला की सुबह ज्यादातर दूसरों से पहले शुरू होती है। घर के सभी काम, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और फिर समय पर कार्यालय पहुंचना यह सब एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। ऑफिस में भी उन्हें अपना काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना पड़ता है। दिन भर की थकान के बाद भी वे घर आकर दोबारा घरेलू कार्यों में शामिल हो जाती हैं। यह दोहरी जिम्मेदारी कभी-कभी महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक दबाव का कारण

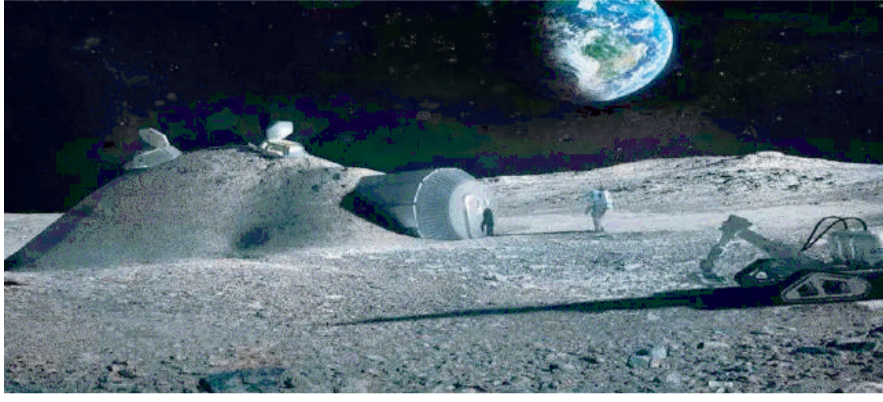
बनती है। समय की कमी, अपने लिए समय न मिलना और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ उनके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देता है। फिर भी, वे हर कठिनाई का सामना अपनी हिम्मत और समर्पण से करती हैं। समाज में अभी भी यह धारणा पूरी तरह से नहीं बदली है कि घरलू काम केवल महिला की जिम्मेदारी है। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी घरेलू कार्यों में भाग लें, तो नौकरीपेशा महिलाओं का जीवन काफी आसान हो सकता है। साथ ही, कार्यस्थल पर भी उनके लिए सुविधाएं और लचीले समय की व्यवस्था होनी चाहिए। आज के समय में महिला सिर्फ घर की देखभाल तक ही सीमित नहीं रही। वह आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। चाहे वह विज्ञान, शिक्षा, बैंकिंग या राजनीति का क्षेत्र हो। लेकिन जब एक महिला घर से बाहर काम करने जाती है, तो उसकी जिम्मेदारियां कम होने के बजाय

दोगुनी हो जाती हैं। घर और कार्यालय के बीच संतुलन: एक नौकरीपेशा महिला के लिए दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है। रसोई का काम, बच्चों को तैयार करने और बुजुर्गों की देखभाल करने के बाद वह अपने कार्यालय के लिए रवाना होती है। कार्यालय में वह अपनी पूरी मेहनत और योग्यता के साथ काम करती है, लेकिन शाम को घर लौटने पर ही वह फिर से 'गृहिणी' की भूमिका में आ जाती है। मानसिक और शारीरिक बोझ दोहरी भूमिका निभाते हुए महिलाएं अक्सर 'सुपरवूमन' बनने की कोशिश करती हैं। इस दौड़ में वे अपने स्वास्थ्य और आराम को पीछे छोड़ देती हैं। थकान: पूरे दिन काम करने के बाद भी रात में घर के कामों की चिंता करना मानसिक थकान का कारण बनता है। अपराध बोध: कभी-कभी काम की व्यस्तता के कारण वे बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते, जिससे उन्हें अंदर से दोषी महसूस

होने लगता है। सामाजिक चुनौतियां हमारा समाज अभी भी पूरी तरह से मानसिक रूप से विकसित नहीं हुआ है। आज भी यह अपेक्षा की जाती है कि महिलाएं अपने घर की बड़ी अधिकारी कर्मांडो न हों, घर का सारा काम उसकी जिम्मेदारी होती है। कार्यस्थल पर भी कभी-कभी महिलाओं को पूर्वाग्रह या काम समझा जाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नौकरीपेशा महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं। वे अपने घर और काम दोनों को अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी कुशलता, उत्साह और समर्पण हमें सिखाता है कि किसी भी कठिनाई को इरादे के बल से जीया जा सकता है। समाज का कर्तव्य है कि वह उनका सम्मान करे और उन्हें समाज अधिकार और सुविधाएं प्रदान करे। डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब



चंद्रमा के गुप्त जलाशय अगली अंतरिक्ष यात्रा को शक्ति प्रदान करते हैं



डॉ. विजय गर्ग
शुक्रो के चंद्रमा को एक बंजर और शुष्क संसार माना जाता था। लेकिन हाल की वैज्ञानिक खोजों ने इस धारणा को नाटकीय रूप से बदल दिया है। चंद्रमा की सतह पर पानी का पता चलने से न केवल पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी के बारे में हमारी समझ बदल गई है, बल्कि मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने में वैश्विक रुचि भी जागृत हुई है। चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की पुष्टि सबसे पहले चांद्रयान-1 जैसे मिशनों और बाद में नासा द्वारा किए गए अवलोकनों के माध्यम से हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि पानी कई रूपों में मौजूद है, जैसे ध्रुवों के निकट स्थायी रूप से छायांकित गड्ढों में बर्फ के रूप में जमी हुई है और यहां तक कि सूर्य की रोशनी वाली मिट्टी में फंसे अणुओं के रूप में भी। इस खोज ने उस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी कि चंद्रमा पूरी तरह सूखा था। हाल ही में, अंतरिक्ष एजेंसियों ने इन जल भंडारों का पता लगाने और मानचित्रण करने के प्रयास बढ़ाए हैं। नासा के लूनार ड्रैगनर और आगामी रोवर-आधारित अन्वेषण जैसे मिशनों का उद्देश्य यह पहचानना

है कि पानी कहाँ केन्द्रित है और चंद्र सतह पर वह कैसे व्यवहार करता है। ये प्रयास सिर्फ वैज्ञानिक नहीं हैं। वे रणनीतिक हैं। जल टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण की कुंजी है। इसका उपयोग पीने, सांस लेने योग्य ऑक्सीजन उत्पादन और यहां तक कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके रॉकेट ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से सभी आवश्यक संसाधनों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मिशन की लागत और जटिलता में काफी कमी आएगी। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। वहां गहरे गड्ढे स्थायी छाया में रहते हैं, जो बर्फ के भंडार को संरक्षित करते हैं, जो संभवतः अरबों वर्षों से मौजूद थे। ये जमे हुए भंडार दीर्घकालिक मानवीय उपस्थिति का समर्थन कर सकते हैं तथा मंगल ग्रह और उससे आगे के मिशनों के लिए ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में काम कर सकते हैं। व्यावहारिक उपयोगों के अलावा, चंद्र जल की खोज का भी वैज्ञानिक महत्व है। इसका अध्ययन करने से

पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति और सौरमंडल के इतिहास के बारे में सुराग मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का पानी धूमकेतु के प्रभाव या सौर वायु कणों से उत्पन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं से आया हो सकता है। परिणामस्वरूप, चंद्रमा अब केवल अतीत की महिमा का गंतव्य नहीं रह गया है। यह भविष्य के लिए एक द्वार बन रहा है। नासा, इस्रो और जैक्सपए के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चंद्रमा पर निरंतर मानवीय उपस्थिति बनाने की साझा दृष्टि को उजागर करता है। निष्कर्षतः, जल की खोज ने चंद्रमा को एक निरर्थक उपग्रह से बदलकर अन्वेषण और नवाचार के लिए एक आशाजनक केंद्र बना दिया है। यह महत्वपूर्ण संसाधन है जो मानवता को इस बड़े चंद्र सतह पर लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है, न केवल आने के लिए, बल्कि रहने के लिए भी। डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाशास्त्री स्टीट कोर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

चुनाव आयोग बनाम डिजिटल प्रचार : क्या नियम अप्रासंगिक हो चुके हैं?

डॉ. शैलेश शुक्ला
भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी — उस समय जब चुनाव प्रचार का अर्थ था दौड़ों पर पोस्टर, नुक्कड़ सभाएँ और अखबारों में विज्ञापन। उस युग के लिए जो नियम बनाए गए थे, वे अपने समय की दृष्टि से अत्यंत उचित और प्रभावी थे लेकिन आज, जब चुनाव प्रचार का केंद्र फेसबुक की वॉल, व्हाट्सएप के समूह, यूट्यूब के चैनल और इंस्टाग्राम की रील बन चुके हैं तो यह प्रश्न बिल्कुल उचित और अत्यावश्यक है कि क्या चुनाव आयोग के पास इस नई डिजिटल वास्तविकता से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार, संसाधन और नियम हैं? उत्तर, दुर्भाग्य से, काफी हद तक नकारात्मक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और आदर्श आचार संहिता (एम्पसीसी) भारत में चुनाव प्रचार के मुख्य नियामक उपकरण हैं। आदर्श आचार संहिता में चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में कई प्रावधान हैं — जैसे कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर मतों की अपील न करना, मतदाताओं को रिश्वत न देना, और चुनाव खर्च की सीमा का पालन करना लेकिन ये प्रावधान मुख्यतः भौतिक दुनिया — रैलियों, पोस्टरों, होर्डिंगों, और प्रसारण मीडिया — को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। डिजिटल प्रचार के कई रूप इन नियमों के स्पष्ट दायरे से बाहर हैं। चुनाव खर्च की सीमा का उदाहरण लें। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये (बड़े राज्यों में) और 75 लाख रुपये (छोटे राज्यों में) निर्धारित थी लेकिन डिजिटल विज्ञापनों का एक बड़ा हिस्सा उम्मीदवारों के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर, तीसरे पक्ष के संगठनों के नाम पर, या बिल्कुल अनाम रूप से चलाया जाता है। व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार का कोई मौखिक मूल्यांकन संभव नहीं है और इसे खर्च की सीमा में शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार, डिजिटल माध्यम चुनाव खर्च की सीमा को अप्रासंगिक बना देता है। 2019 के आम चुनाव में एंटी-डिजिटल फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की एकरिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक दलों द्वारा फेसबुक और गूगल पर घोषित डिजिटल विज्ञापन खर्च का जो आँकड़ा चुनाव आयोग को दिया गया, वह वास्तविक खर्च से काफी कम था। फेसबुक की स्वयं की 'एड लाइब्रेरी'



रिपोर्ट से पता चला कि केवल भाजपा और कांग्रेस ने उस चुनाव के दौरान फेसबुक पर करोड़ों रुपये के विज्ञापन दिए थे लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग को दी गई खर्च विवरणों में शामिल नहीं था। यह नियामक प्रणाली की एक मौलिक खामी को उजागर करता है। पेड न्यूज की समस्या, जो पहले मुख्यतः प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में थी, अब डिजिटल माध्यमों में भी विकराल रूप ले चुकी है। डिजिटल न्यूज पोर्टलों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसरों' को राजनीतिक प्रचार के लिए पैसे देना और उसे 'समाचार' या 'विचार' के रूप में प्रस्तुत करना बेहद आसान हो गया है। चुनाव आयोग के पेड न्यूज से संबंधित प्रावधान मुख्यतः पंजीकृत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू होते हैं। हज़ारों अनाम या कम-ज्ञात डिजिटल प्रकाशकों और सोशल मीडिया खातों पर इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना लगभग असंभव है। साइलेंट पीरियड — यानी मतदान से 48 घंटे पहले का वह समय जब राजनीतिक प्रचार बंद होना चाहिए — डिजिटल युग में भी एक बड़ी चुनौती है। टेलीविजन और रेडियो पर इसे लागू करना अपेक्षाकृत सरल है लेकिन सोशल मीडिया पर यह नियम व्यावहारिक रूप से कागजि बन जाता है। पुराने पोस्टर और वीडियो स्क्रीनलेट होते रहते हैं, नए 'स्पॉन्सर्ड' कंटेंट अप्रत्यक्ष रूप से जारी रहते हैं और व्हाट्सएप समूहों में तो किसी प्रकार की कोई रोक संभव ही नहीं है। 2019 और 2024 दोनों चुनावों में इस नियम के उल्लंघन की अनेक शिकायतें आईं लेकिन कार्रवाई नगण्य रही। चुनाव आयोग ने इस बदलती परिस्थिति

के प्रति पूरी तरह आँखें नहीं मूंदी हैं। 2019 के चुनाव के पहले आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ एक 'स्वैच्छिक आचार संहिता' पर हस्ताक्षर किए और एक 'सोशल मीडिया कमेटी' का गठन किया। 2024 के चुनाव के लिए मेटा, गूगल, और अन्य कंपनियों के साथ समझौते किए गए लेकिन ये समझौते स्वैच्छिक हैं, इनमें कानूनी बाध्यता नहीं है, और इनका क्रियाव्यवहन अस्पष्ट रहा है। जब कोई कंपनी चुनाव आयोग के अनुरोध पर कोई सामग्री हटाने से इनकार करती है तो आयोग के पास सीमित विकल्प होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कई लोकतांत्रिक देशों में डिजिटल प्रचार के नियमों के लिए अधिक व्यापक प्रावधान हुए हैं। यूरोपीय संघ ने 'डिजिटल प्रचार एडवर्टाइजिंग ट्रान्स्पैरेंसी रेगुलेशन' पारित किया है जो राजनीतिक विज्ञापनों में अनिवार्य प्रकटीकरण (डिसक्लोचर) की माँग करता है। कनाडा ने 'इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्नाइजेशन एक्ट' में ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पंजीकरण और पारदर्शिता की अनिवार्य आवश्यकताएँ जोड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में 'डिजिटल प्रचार सामग्री पर भी 'प्रयोजित' लेबल अनिवार्य है। भारत में ऐसे व्यापक और बाध्यकारी कानूनी प्रावधान अभी भी नहीं हैं। डिजिटल राजनीतिक विज्ञापनों को पारदर्शिता का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। फेसबुक की 'एड लाइब्रेरी' और गूगल की 'ट्रान्स्पैरेंसी रिपोर्ट' कुछ जानकारी देती हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं पर होने वाला राजनीतिक प्रचार बिल्कुल अपारदर्शी है। एक अनुमान के

अनुसार, भारत में 2024 के चुनाव के दौरान व्हाट्सएप पर प्रतिदिन करोड़ों राजनीतिक संदेश प्रसारित होते थे लेकिन उनमें से कितने निगरान किए गए थे और कितने भुगतान किया था — यह जानने का कोई तरीका नहीं था। माइक्रोटॉगेंड राजनीतिक विज्ञापन चुनाव आयोग के लिए एक और अनसुलझी चुनौती है। जब कोई राजनीतिक दल फेसबुक पर एक विशेष जाति या धार्मिक समूह को लक्षित करके ऐसे विज्ञापन दिखाता है जो सार्वजनिक नहीं हैं तो चुनाव आयोग इसकी जाँच कैसे करे? आदर्श आचार संहिता का वह प्रावधान जो जातीय या धार्मिक आधार पर वोट माँगने को मना करता है, उन विज्ञापनों पर कैसे लागू हो जायेगा? विशेष 'डिजिटल मॉनिटरिंग सेल' जिसमें डेटा वैज्ञानिक, सोशल मीडिया विशेषज्ञ और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हों — यह आज की जरूरत है। साथ ही, प्रत्येक राज्य और जिला स्तर पर डिजिटल प्रचार की निगरानी की क्षमता विकसित करनी होगी लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि तकनीकी निगरानी की अपनी सीमाएँ हैं — जब प्रचार का पैमाना अरबों संदेशों और करोड़ों उपयोगकर्तों तक फैला हो, तो किसी भी नियामक संस्था के लिए पूर्ण नियंत्रण असंभव है।

जलवायु परिवर्तन: पान की पारंपरिक खेती खतरे में



राजस्थान में पान की खेती जलवायु परिवर्तन की मार से सिमट रही है लेकिन नीतिगत अनदेखी ने संकट को और गहरा दिया है। गांवों में यह खेती छूट रही है, गांव खाली हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किसानों को अकेला छोड़ दिया गया है? अमरपाल सिंह वर्मा वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील के कुछ गांव आजकल किसी रिपोर्ट के आंकड़े नहीं बल्कि एक धीमी त्रासदी की तरह सामने आते हैं। कभी यहाँ पान की बेलें सिर्फ खेतों में नहीं, लोगों की जिंदगी में भी लहलहाती थीं। आज वही बेलें सिकुड़ गई हैं और उनके साथ सिकुड़ गई है एक पूरे समुदाय की आर्थिक और सामाजिक दुनिया। एक आज के गांव खाली हो रहे हैं। वहाँ के ग्रामीण कामकाज के लिए बड़े शहरों में पलायन कर गए हैं। खाली पड़े मकान गांवों को भुतहा सा दर्शाते हैं। पिछले दिनों मैंने जब इस इलाके के बारे में सुना था तो एक बात बार-बार मन में आ रही थी कि क्या सचमुच यह सिर्फ मौसम की मार है? या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को 'जलवायु परिवर्तन' जैसे बड़े शब्दों के पीछे छिपा रहे हैं? यह सच है कि मौसम बदल गया है। सदियों पहले जैसी नहीं रही है, गर्मियाँ झुलसा देती हैं और बारिश अपने समय पर नहीं आती। पान जैसी नाजुक फसल के लिए यह बदलाव जानलेवा साबित हुआ है। मैं जब इस इलाके में गया तो गांवों की समृद्ध अर्थव्यवस्था को उजड़ते हुए पाया। खरैरी, बागरेन और खानखेड़ा गांवों के किसान बताते हैं कि पहले पान की एक बेल पंद्रह फीट तक जाती थी, अब सात-आठ फीट पर ही दम तोड़ देती है। पत्ते कम हो गए हैं, और जो हैं, वे भी अक्सर दागदार या जले हुए मिलते हैं।

लेकिन यहाँ कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ किसान मौसम से लड़ने-लड़ते थक जाता है और फिर उसे अहसास होता है कि इस लड़ाई में वह अकेला है। कोई उसके साथ नहीं है। पान की खेती आज भी फसल बीमा के दायरे से बाहर है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर हैरानी नहीं बल्कि चिंता होनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि जब जोखिम बढ़ रहा है, तब सुरक्षा का दायरा क्यों नहीं बढ़ता? क्या हमारी नीतियाँ केवल लक्ष्य हैं? क्या मुख्यधारा की फसलों तक सीमित रह गई है? या फिर हम उन फसलों को नजर अंदाज कर रहे हैं, जो भले ही राष्ट्रीय आंकड़ों में बड़ी न दिखें लेकिन स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं? बयाना का खरैरी गांव इसका जीता-जागता उदाहरण है। कभी यहाँ पान की वजह से इतनी रौनक थी कि बैंक की मुद्रा शाखा तक खुल गई थी। आज हालात ऐसे हैं कि वह बैंक भी अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुका है। यह सिर्फ एक आर्थिक गिरावट नहीं, बल्कि एक पूरे दौर के खत्म होने की निशानी है। इसके बाद आता है पलायन। गांव के युवा अब खेतों में नहीं, शहरों की भीड़ में मिलते हैं। बड़े शहरों में कोई सिक्कोरिटी गार्ड है, कोई हलवाई के यहाँ काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। यह बदलाव सिर्फ पेशे का नहीं है बल्कि पहचान का भी है। जो लोग कभी अपने खेतों के दम पर समृद्ध थे, वे अब शहरों में मजदूरों की कतार का हिस्सा बन गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या हम गांवों को धीरे-धीरे खाली होते देखने के आदी हो चुके हैं? सरकार की भूमिका पर बात करना यहाँ जरूरी है लेकिन इसे केवल आलोचना के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखा चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में सदियों पुरानी खेती खत्म होने के कारण पर है तो क्या यह सिर्फ किसानों की समस्या है? या यह नीति-

निर्माताओं के लिए भी एक चेतावनी है? पान की खेती को अगर बीमा, अनुदान, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ा जाता तो शायद हालात यह न होते। आसपास मंडी नहीं है, परिवहन की सुविधा कमजोर है — ऐसे में किसान अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भर है। इससे लागत बढ़ती जाती है, मुनाफा घटता जाता है और अंततः किसान खेती छोड़ देता है। हमें कई सवालों पर विचार करने की जरूरत है। क्या हम केवल संकट के बाद राहत हमारी नीतियाँ केवल लक्ष्य हैं? अंतर सोचें तो इन सवालों के जवाब और समस्या का समाधान बहुत जटिल नहीं है लेकिन इरादा तो होना चाहिए। पान जैसी खेती को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार और नीति निर्माताओं को मिल कर प्रयास करने होंगे। सबसे पहले जरूरी है कि पान जैसी फसलों को फसल बीमा के दायरे में लाना जाए। ऐसा करके हम किसानों को कोई अहसास नहीं करोगे बल्कि यह तो न्यूनतम सुरक्षा है, जो उन्हें मिलनी ही चाहिए। इसके साथ-साथ जलवायु के अनुरूप खेती के तरीकों पर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और शोध की जरूरत है। इसके अलावा, छोटे-छोटे कृषि केंद्र और मीडिया विकसित करनी होंगी जिससे किसानों को बाजार से जोड़ा जा सके। बयाना के गांवों का अनुभव कड़वा है। जब खेतों में पान के पत्ते जलते हैं तो वहाँ सिर्फ फसल नहीं जलती, उसके साथ कई उम्मीदें, परंपराएँ और भविष्य की झुलस जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने ही होंगे। अमरपाल सिंह वर्मा (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राजा सरायकेला का भैरव समक्ष ऐतिहासिक पूजा के साथ विश्व प्रसिद्ध सरायकेला छऊ का शुभारंभ

राजा तो इतिहास को जीवनदान कर गये पर उन परिवारों, संरक्षकों, जानकारों को सरकारी आयोजन से दूर क्यों ?

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड-झारखंड

सरायकेला, सरायकेला राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव ने अपनी राजकीय परंपरा अनुसार सरायकेला के पुर्व दिशा में स्थित रमशान भूमि समीप अखाड़ा साल में भैरव देव संग ढाल खंडा (एक तरह का उत्कलीय तलवारों की) की विधिवत पूजा अर्चना की । उत्कलीय संस्कृति व शक्तियों पुरानी कलिंग सभ्यता अनुभव जगन्नाथ जी के उत्कलीय नववर्ष आगमन (महा विषुव पणा संक्रांति) पूर्ण सरायकेला राजकीय घट पाट आयोजन के साथ विश्व प्रसिद्ध छऊ का मूल एक अखाड़ा अष्ट भैरव समक्ष यजमान के रूप में उन्होंने अपना माथा टेका । उत्कलीय खंडायत, पाइक सैन्य परंपरा का यह बेजोड़ नमूना रहा है । जिसे देखने विदेशी जहां लालयित थे वहीं देश के प्रख्यात पत्रकार, लेखक ने देश विदेश से यहां आकर अपनी अनमोल छाप छोड़ी है । आज जब राजा घर में उपजा छावनी का छऊ सरकार आयोजन में षड्यंत्र पूर्वक मित रहा है ऐसे में यहां उसके समर पिपासु खंडायतों के फरिखंडा से जन्मा छऊ फिर नर्तक व उपासक दोनों यहां तलवार उठाकर नाचते हैं । जहां पाईक अखाड़े जीवन हो उठते हैं ।

डेढ़ सप्ताह तक चलने वाली विश्वप्रसिद्ध सरायकेला छऊ उत्सव का शुभारंभ हो गया । राजा सरायकेला प्रताप आदित्य सिंह देव उनके अनुयाई वर्ग । इतिहास धारक परिवारों बेजोड़ समावेश यहां देखने को मिला । यह वही सांकेतिक पूजा रही है जब उड़ीसा के रणविक्रु युद्ध जाने के पहले ढाल तलवार की पूजा कर । उसमें भैरव भैरवियों को स्थान देते थे । उन्हें शत्रुओं के रक्त पिलाने हेतु सीधे रमशान पूजारी की रूप में इतिहास में गिने जाते रहे । यह किसी रियासत की राजकीय पूजा एवं उसका सामरिक उत्सव होता था जिसे बखूबी राजा

सरायकेला के जरिए सरायकेला की पब्लिक दिल से आयोजन करती है । आज सरायकेला राजमहल के राजागण और जगन्नाथ के सीमा सुरक्षा प्रहरी खंडायत गण रहे जिनका इतिहास को आजाद मुल्क में बिहार के बाद झारखंड सरकार समान्य करने में तुली हुई है , नतीजतन आज एक भी विदेशी पर्यटक अब यहां नहीं आते । कभी इसी पूजा में उन लोगों की भीड़ व उत्सुकता परिलक्षित होती थी । यह भले ही सांकेतिक पूजा होता है भैरव भैरवियों एवं रमशान गणों का पर इसका वास्तविक इतिहास उस कलिंग, उत्कल के वीरों के साथ जुड़ा हुआ है जिनका साम्राज्य कभी गंगा से गोदावरी तक जीत के बाद फैला हुआ था । नाम था कलिंग । यह ढाल तलवार उत्तर कलिंग का हिस्सा रहा जो ओडिशा के पाईक वीरों का था । सरायकेला राजा स्वयं यजमान के तौर पर अखाड़ा साल में पूजा आरंभ की और रणविक्रु खंडायतों वीरों की सामरिक इतिहास धारक तथा मार्शल आर्ट के नर्तक भी ढाल तलवार पकड़ कर सामरिक युद्ध प्रदर्शन करते रहे जिसे फरिखंडा कहा जाता है । फिर सबने साथ में भैरव अखाड़े में अन्न प्रसाद ग्रहण किया ।

सरायकेला स्टेट विलय 15 दिसंबर 1947 के बाद यह ओडिशा का एक जिला रहा । जहां ओडिया संस्कृति को ओडिशा के तर्ज पर ध्यान रखने का विलय दस्तावेज भी वर्णन है । प्रथम उपायुक्त ओडिशा कैडर के तेजतर्रार अधिकारी दुर्गा दास रहे । फिर इसे एक षड्यंत्र रच कर बिहार लाया जाता है एक वर्ष के लिए पर आज तक नहीं लौटाया गया । इसी बीच अन्तिम शासक राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव, फिर साथ में उनके पुत्र टिकाप्रताप नृपेंद्र नारायण सिंहदेव, उनके मौजूदा राजा साहब प्रताप आदित्य सिंहदेव आज भी संस्कृति को यथावत बनाए हुए हैं । जहां सरायकेला ही नहीं भारत वर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के कला संस्कृति के पूजार्थियों का लगाव व ध्यान रहते देखा जा सकता है । इसी पूजा को आज राजा सरायकेला ने परंपरा अनुसार निर्वाह किया ।



सच तो यह है कि सरायकेला स्टेट के समय एक गडबिषय का पद हुआ करता था जिसे सरकार ने राजा घर से अपना छऊ को षड्यंत्र पूर्वक लेजाकर उक्त पद को खत्म किये हुए है । जो सरायकेला मार्जार एग्रीमेंट का घोर उलंघन है अगर छऊ एवं परंपरा का कोपीराईट सरायकेला ओडिया स्टेट से जुड़ा है । गडबिषय मूलत उत्कलीय क्षत्रिय खंडायत होते । तलवारबाज कला के उस्ताद ओडिशा शाही परिवारों के शाही खंडायत सरदार यहां होते थे आज कहां किस हाल में हैं वे खोजने से इतिहास को भी नहीं मिलेगा षड्यंत्रकारियों के कारण । जिन्हे संरक्षण एवं संवर्धन देना चाहिए था Instrument of Excession of Seraikella State के तहत । इसपर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के क्रियाकलाप पर अविबल्वन्धन देने की जरूरत है । पर ऐसा नहीं हो पाना घोर अन्याय है । ओडिशा में ये (जो प्रमुख बेहारा/दलबेहारा/पाईकराय हैं वे पाइक वीर

माने जाते) । सरायकेला के अन्तिम शासक जिन्होंने अपना राज्य स्वतंत्र भारतवर्ष में सरदार पटेल के समक्ष ओडिशा में दिया उस समय एवं उनके कार्यकाल में सरायकेला के शशिभूषण दरोणा गडबिषय रहे । इस पूजन कार्यक्रम का आयोजन वही करता थे । जिनको इंग्लैंड में बैट्री गोरी महारानी की सरकार The Domestic officer of Seraikella थी । सरायकेला के रूप में भली भाली जानती थी । सरायकेला जनता को हैरानी इस बात की है कि आज नतो जानकार रह गये जो इसे बता सके नाही सरकारी तंत्र में पत्रकार , लेखक । और जो रह गये सरकार उनके जरिए क्या करती जग जाहिर है । ऐसा मानना है चार करोड़ ओडिया के बुद्धिजीवियों का विश्व भर में । यद्यपि सरायकेला में ओडिया संस्कृति को तहस नहस करने का सिलसिला जारी है । जिसे आम मूलवासी नागरिकों कुपित होते देखा जा सकता है ।

अनोजीगुडा स्थित पोचराम पुलिस स्टेशन C । कंनकाया गौड़ ने पद ग्रहण किया इस अवसर कोरेमुला बडेर अध्यक्ष कालुराम काग, कमल किशोर अगलेचा, दिनेश काग द्वारा राजस्थानी साफा पहनाकर, शाल व मोमेंटो द्वारा सम्मान किया ।



दुकानों और कर्मशियल जगहों पर ओडिया नेमप्लेट लगाने के लिए जागरूकता वाक निकाली गई



मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: पूरे राज्य में 1 अप्रैल 'ओडिशा डे' से 14 अप्रैल 'ओडिया न्यू ईयर' तक 'ओडिया डे-2026' मनाया जा रहा है । इस मौके पर, लेबर और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आज सभी दुकानों और कर्मशियल जगहों पर ओडिया में नेमप्लेट साफ-साफ लगाने के लिए एक बड़ा जागरूकता कैम्पेन और वाक सफलतापूर्वक निकाली गई । लोअर P.M.G से लेबर ऑफिस के ऑफिस तक निकाली गई इस वाक में 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और ओडिया भाषा को फैलाने का वादा किया । जागरूकता वाक का औपचारिक उद्घाटन लेबर ऑफिस के श्री इंद्रमणि त्रिपाठी ने किया । उद्घाटन समारोह में अपनी स्पीच देते हुए उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट के अधिकारी 4 अप्रैल से 7

अप्रैल, 2026 तक चार दिनों तक अलग-अलग दुकानों और कर्मशियल जगहों पर जाएंगे । जहां ओडिया नेमप्लेट साफ-साफ नहीं लगी है, वहां व्यापारियों से ओडिया नेमप्लेट साफ-साफ लिखने की रिक्वेस्ट की जाएगी । उन्होंने कहा कि हमारी भाषा हमारी पहचान और शान है, इसलिए हर बिजनेस वाली जगह पर इसका इस्तेमाल पक्का करना हम सबकी जिम्मेदारी है । इस मौके पर एडिशनल लेबर ऑफिसर मदन मोहन पैक, जॉइंट लेबर ऑफिसर विघ्नजीत महंत महापात्रा और भारती सीता, प्रबन्ध लेबर ऑफिसर बनानी महापात्रा, खोरधा प्रबन्ध लेबर ऑफिसर अजय प्रधान, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर प्रभाकर बिस्वाल, लेबर और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पीयूष परिदा और 'ओडिशा कल्याण' के

नोडल ऑफिसर प्रोतिश पांडा मौजूद थे और उन्होंने प्रोग्राम को कंडक्ट किया । गौरतलब है कि ओडिशा शांप्स एंड कर्मशियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के मुताबिक, हर बिजनेस वाली जगह पर ओडिया में साफ-साफ नेमप्लेट लिखना जरूरी नियम है । एक्ट के सेक्शन 35 के मुताबिक, अगर कोई भी जगह इस नियम को तोड़ती है, तो उसे भारी आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा । नियम का पहली बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये और दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है । इस जागरूकता अभियान के जरिए शहर के व्यापारियों को कानून के बारे में बताया गया है और उनसे ओडिया भाषा की गरिमा की रक्षा करने का आग्रह किया गया है ।

धीरे-धीरे चलती थी रेलगाड़ियां, पर दर्द बहुत तेज भागता था

दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति महाविद्यालय ने अक्षरम में प्रस्तुत किया बंटवारे का दर्द

हरियाणा/हिंसार (राजेश सलुजा) : उन्होंने एक लकीर खींच दी, जल्दी में बिना सोचे समझे, नदियों का खयाल किया, नारिश्तों का कोई मान रखा, घर टूट गए, आंगन सूने थे, यादें साथ थी, पर दिल टूटे थे, धीरे-धीरे चलती थी रेलगाड़ियां, पर दर्द बहुत तेज भागता था ।

विभाजन की विभिधिका को दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुछ इस तरह मंच पर उतारा । महाविद्यालय ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जारी अक्षरम-2026 में साहित्यकार यशपाल के उपन्यास झुंदा सच पर आधारित बंटवारे का दर्द नाटक का मंचन किया । हरविंदर कोर निर्देशित यह नाटक लाहौर की गलियों से प्रारंभ होकर विभाजन के दौरान बिछड़े परिवारों, विस्थापन, सांप्रदायिकता और उस समय की वेदना का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है । इस नाटक में कलाकारों ने बंटवारे के दर्द और ईशान्वित के संघर्ष को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया । नाटक में कलाकारों के डायलॉग पहली दरार हमेशा छोटी होती है, पर वही दरार, दीवारें गिरा देती हैं ने विभाजन के समय शुरू हुए झगड़ों की जड़ को रेखांकित किया । वो आंगन बचन बचपन खेला, वो चौखट जहां मां ने दीप जलाया था, वो खिड़की जिससे हर सुबह सूरज ने



सपना दिखाया, सब पीछे छूट गया था एक दिन, बस आंसू संग ले जाना था, नफरत की जलती आँधियों में अपना ही घर बेगाना था, पंक्तिओं से कलाकारों ने विभाजन की त्रासदी के गवाह बनने वालों के दर्द को बयां किया । अचानक खबर आई जैसे बिचली सी गिर गई, एक लकीर खींचने वाली है, धरती मां दो हिस्सों में बंट गई, ने विभाजन की पूरी वेदना बयां कर दी ।

सूत्रधार निशु एवं प्रिया ने दर्शकों को कलाकारों से जोड़े देखा । अंत में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. नीलम राठी ने कलाकारों का परिचय करवाया जिनमें प्रतिमा ने जयदेव, अंजलि ने कनक, श्रुति ने तारा, जेलन ने मास्टर रामभुलाया, पारमिता ने अम्मा, नदिनी ने असद व सुद, मुस्कान ने पांडे व वृद्ध पुरुष और स्त्री का किरदान निभाया । इसी प्रकार

साक्षी, प्रिया, राजनंदनी, इशिका, निशा, शिवनी, रितु, प्रीति, आफरिन, शिखा, गुंजन, गौराक्षी और निशु का भी परिचय दिया । कॉलेज टीम में प्रोफेसर रजनी राठी व मंच से परे कार्य करने वालों में संतोष कुमार सिंह, रमेश मनचंदा, हरविंदर कोर, रामभुलाया, पारमिता ने अम्मा, नदिनी ने असद व सुद, मुस्कान ने पांडे व वृद्ध पुरुष और स्त्री का किरदान निभाया । इसी प्रकार

कानपुर में नौकरी के बहाने देह व्यापार के दल - दल में ढकेली गई पश्चिम बंगाल की हसीना, यूट्यूबर गिरफ्तार, जांच जारी

सुनील बाजपेई

कानपुर । कमसिन लड़कियों से देह व्यापार कराने में अग्रणी गिरोह ने नौकरी दिलाने के बहाने पश्चिम बंगाल की एक व्यक्ति को देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया मामले में पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दादा के नाम से चर्चित सरगना बताए जाने वाले पश्चिम बंगाल के एक अन्य व्यक्ति समेत और भी कई लोगों की तलाश लगातार जारी है । अब तक की जांच के दौरान लगभग 20 होटल के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जहां लड़कियां सप्लाई की जाती थीं । पुलिस के अनुसार युवती को 'कोलकाता के दादा' नाम से पहचान रखने वाले व्यक्ति और कानपुर निवासी रोहित वर्मा ने नौकरी का झांसा दिया था । इसके बाद भी वह पश्चिमबंगाल से कानपुर आई थी । लेकिन यहां उसे बंधक बनाकर जबरन



गलत धंधे में धकेल दिया गया । आरोप है कि उस पर लगातार दबाव बनाया जाता था और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी । साथ ही उसे जान से मारन की धमकी भी दी गई थी । जानकारी के मुताबिक मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती किसी तरह मौका पाकर आरोपियों के चंगुल से निकल गई और सीधे पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एडीसीपी क्राइम सुमित सुधाकर रामटेके, एडीसीपी लाइन शिवा सिंह और ट्रेनी आईपीएस सुमेध एम जाधव के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया । इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इंदिरा नगर क्षेत्र से आरोपी रोहित वर्मा को हिरासत में लिया । वहीं, 'कोलकाता के दादा' की गिरफ्तारी के लिए एक टीम पश्चिम बंगाल रवाना की गई है । पूछताछ

में आरोपी ने पहले खुद को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में कई अहम जानकारियां दीं । गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से पुलिस को एक न्यूज पोर्टल का आईडी कार्ड और मोबाइल नंबरों की सूची मिली है । इसके आधार पर कल्याणपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां कुछ अनियमितताएं सामने आईं । पुलिस ने संबंधित होटलों के बुकिंग रजिस्टर और अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं । मामले में पुलिस की गहन छानबीन के दौरान लगभग 20 होटलों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है । साथ ही अन्य पीड़िताओं और संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है । प्रारंभिक जांच में इस रैकेट के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की आशंका के आधार पर पूरे नेटवर्क की गहन जांच में लगातार जारी है ।

